12.14 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ACUTE POWER SHORTAGE AND INCREASE IN ELECTRICITY RATES IN HARYANA AND OTHER PARTS OF THE COUNTRY.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर उर्जा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें--हरियाणा और देश के अन्य भागों में बिजली की भारी कमी और बिजली की दरों में वृद्धि, जिसके कारण किसानों में रोष व्याप्त है और फसलों को नुकसान हो रहा है तथा उत्पादन कम हुआ है, का समाचार''

श्री आर. एन. राकेश (चैल): (व्यवधान)**

12.15 hrs

[Shri R. N. Rakesh then left the House]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर): (व्यवधान)**

(Shri Rajnath Sonkar Shastri then left the House).

THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): Sir, I fully share the anxiety of the Hon'ble Members regarding the shortage of power being experienced in some of the States of the country. In the beginning of last year when the present Government took over, most of the States were facing severe shortages of power, which was affecting industry and agriculture. This was a legacy of the Janata Rule inherited by us. The capacity utilisation of thermal power stations in the country, which had reached a record figure of 56 per cent in the year 1976-77, steadily came down to nearly 45 per cent in 1979-80. The drought of 1979 also affected the availability of hydro-generation in the early part of 1980, because of reduced reservoir levels.

2. A number of short-term and long-term measures were initiated to improve power availability. I am glad to say that, as a result of measures taken by us there have been continuous improvement in power availability in the country since September 1980 onwards. In the recent months the improvement has been very significant, for example, the increase of overall generation over the corresponding period last year has been about 20 per cent in November 1980, 16 per cent in December 1980, 10 per cent in January 1981 and over 10 per cent during February 1981. The improvement in thermal generation, which is substantially dependent on human effort, was even more as shown in the corresponding figures of 21.7 per cent, 22.3 per cent, 14.5 per cent and 12.8 per cent, respectively. I am glad to tell you that the shortage of power during December 1980 was about 11 per cent only as against 23 per cent shortage during December 1979. Similarly in January 1981 the shortage of power was about 14 per cent as against 21 per cent during january, 1980.

3. In spite of this improvement and upward trend, which is continuing, we are not fully satisfied. There has been a constant dialogue with the States and the State Electricity Boards, who are directly responsible for power generation. We have also given detailed guidelines to States for specific steps to be taken for maximing generation, and completion of on-going projects on schedule. I have also convened two all India Conferences and four Regional Conferences of State Power Ministers during the current year at which the discussions have centered round on concrete steps to increase capacity utilisation to narrow the gap between power availability and power requirements.

4. Regarding tariff, the House is aware that this is a matter within the

**Not recorded.

[Shri Vikram Mahajan]

purview of State Governments. Every state is trying to mobilise resources for expansion of the electricity industry. However, there is an All India pattern that the agricultural sector enjoys concessional tariff compared to other classes of consumers and also as compared to the cost of power supply. So far as the agricultural sector in Haryana is concerned, they had increased the tariff rates with effect from 1st January 1981 but have now reduced the agricultural tariff to the previous level. The increase in the other tariffs, is within the competence of the State authorities. As a Central Minister, I cannot interfere in this issue which is entirely within the purview of the State Government. From our side, we have requeted the State Governments to ensure minimum power supply of six to eight hours per day for the agricultural sector. We have also deployed special teams from the Rural Electrification Corporation to monitor power supply to the agricultural sector and to see that the states are in fact complying with our request. I am happy to say that the power supply position to the agricultural sector in most of the states is satisfactory. This has been discussed in the Power Ministers' Conferences also, and we have found that the position was satisfactory.

श्री राम विलास पासवान: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने सब जगह स्थिति पर संतोष जाहिर किया है और प्रसन्नता व्यक्त की है। मैं देख रहा हूं कि आजकल सरकार के पास हर मर्ज की एक ही दवा है कि विगत सरकार से जो हमें विरासत में मिला है उसका ही यह नतीजा है। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने इकानामिक सर्वे है, आर्थिक समीक्षा है, इसमें आप देखें कि किस-किस वर्ष में कितना बिजली का उत्पादन हुआ है। 1960-61 में 1993 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ, 1975-76 में आप उत्पादन करते थे 7923 मेगावाट और 1979-80 में हम लोगों के शासन काल में उत्पादन हुआ 10471 मेगावाट। यह इकानामिक सर्वे है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज): मैं एक बात माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कितने वर्ष लगते हैं। जो योजनाएं हमने शुरू कीं वे आपके समय में कंप्लीट हो गईं, इस वजह से उत्पादन बढ़ा।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे अब भी अगर अपने जवाब में यह कह दें कि हम खेती को प्राथमिकता देने जा रहे हैं तब भी हमको कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय सहमत नहीं होंगे। मंत्री महोदय ने जो अपने जवाब में कहा है कि यह स्थिति हमको विरासत में मिली है, यह बेबुनियाद और असत्य है। मंत्री महोदय ने हमेशा की भांति अपनी गल्तियों को छिपाने के लिए इस प्रकार का जवाब दिया है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हमने अपनी ओर से राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे कृषि के लिए प्रतिदिन 6 से 8 घंटे बिजली सप्लाई करें लेकिन मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि इंडस्ट्रीज को प्रतिदिन कितनी बिजली देने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है। **(व्यवधान)**

मंत्री महोदय ने कहा है कि किसानों को अधिक से अधिक 5-6 घंटे बिजली दी जाए, यह जवाब में कहा गया है, लेकिन उद्योगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसमें मुख्यत: तीन प्रश्न थे। पहला बिजली के प्रोडक्शन के संबंध में, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में और तीसरा बिजली के रेट्स के संबंध में और चौथा आज जो किसान की तबाही हो रही है और जो हाहाकार मचा हुआ है, उसके संबंध में। माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं एक जगह गए थे, उन्हें प्रेम-पूर्वक ले जाया गया था, उन्होंने वहां की स्थिति देखी है कि आज गांवों में कर्मचारियों को किसानों ने घेरा हुआ है। इसका नतीजा यह है कि लहारा गांव में किसानों पर

गोली चली और फरटिया गांव में हुकुम सिंह नामक किसान मारा गया। इसी प्रकार गांव फाड़ा, थाना घरौंडा, जिला करनाल के टेकचन्द को बिजली मांगने के आरोप में मार दिया गया। वहां पर सी. पी. एम. और सी. पी. आई. के लोग और अन्य लोग जाकर देख आए हैं। इस तरह से बिजली का हाहाकार मचा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, गांवों में एक कहावत है कि यदि कोई आदमी किसी की फसल बरबाद कर दे तो उसको फाटक में बंद कर देते हैं। देहात में अब भी कहते हैं कि कोई जानवर किसी की फसल बरबाद कर देता है तो उसे फाटक में बन्द कर दो। जो सरकार करोड़ों एकड़ किसानों की फसल बरबाद करती है उसे फाटक में बन्द करना चाहिये या नहीं? आप चेयर पर हैं, आप की रूलिंग है। क्या यह किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं है? ऐसी सरकार को फाटक में बन्द किया जाए या नहीं?

12.25 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

हम सब जगह कह रहे हैं कि जो सरकार इस तरीके से काम करे, जो किसानों के खेत में पानी न दे, किसानों को बिजली न दे, बिजली की चोरी करवाए, बड़े बड़े पूंजी पतियों से, बड़े बड़े लोगों से मिल कर उनकी जरूरतों को पूरा करे, कारखानों की जरूरतों को पूरा करे उस सरकार के रहते गांव का पैसा गांव में ही रहना चाहिये, गांव की बिजली गांव में ही रहनी चाहिये, जो कर्मचारी वहां काम करने आता है उस कर्मचारी को फाटक में बन्द करो। ऐसा किया जाएगा तब कुछ होगा।

आर्थिक समीक्षा के मुताबिक 1960-61 में कुल बिजली उत्पादन की क्षमता 4653 मैगावाट थी और उत्पादन हुआ कुल 1693 मैगावाट। 1979–80 में इंस्टाल्ड कैपेसेटी 28468 मैगावाट थी और उत्पादन हुआ केवल 10471 मैगावाट का। पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना चौथी योजना और अभी 1980–81 में आपने जो लक्ष्य रखे थे क्या वे कभी प्राप्त हुए? अगर नहीं हुए तो क्या मंत्री महोदय ने इस पर विचार किया है कि इतने ऊंचे लक्ष्य रखने का आडम्बर नहीं किया जाना चाहिये, डपोर सखिये की तरह बड़ी बातें नहीं की जानी चाहिये और उतना ही टारगेट रखा जाना चाहिये जितने की प्राप्ति हो सकती हो?

आप प्राइवेट सैक्टर को देखें। उस में 85 परसेंट तक प्रोडक्शन होता है लेकिन पब्लिक सैक्टर जिस की आप हमेशा वकालत करते रहते हैं और जितने भी हैं और जिन के बारे में आप कहते हैं कि उनके सामने ये ये डिफिक्लटीज हैं क्या उन में से किसी ने भी 85 प्रतिशत तक का प्रोडक्शन किया है और क्या जो डिफिक्लटीज पब्लिक सैक्टर के सामने हैं वे प्राइवेट सैक्टर के सामने नहीं होती हैं? मैं जानना चाहता हूं कि लक्ष्यों की पूर्ति क्यों नहीं हो पाती है?

किसानों के सम्बन्ध में मेरा प्रश्न है। उनको बिजली कितनी मिलती है? आप का यह 1979-80 का लेटेस्ट सर्वे है। इसके मुताबिक कृषि क्षेत्र को केवल 16.9 प्रतिशत बिजली मिलती है जबकि औद्योगिक घरानों को 59.7 प्रतिशत। इतना बड़ा अन्तर क्यों? हम चाहेंगे कि गांवों के किसानों को प्राथमिकता दी जाए। वह अपने खेत में पैदावार बढ़ाएगा तो उससे देश खुशहाल होगा और देश का औद्योगीकरण आटोमैटिकली होता जाएगा। लेकिन आप तो किसान के खेत में पानी नहीं देते हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं करते हैं। गांव में किसान को कितने घंटे बिजली मिलती है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में तथा दूसरी जगहों पर किसानों को कितने घंटे बिजली मिलती है। एक दिन की बात आप छोड़ दें। महीने का यदि आप हिसाब लगाएं तो कहीं 28 घंटे, कही 32 घंटे हो मिलती है। मैं जहां से आता हूं वहां केले की फसल होती है। बिजली के अभाव के कारण केले की फसल वहां चौपट हो जाती है, बरबाद हो जाती है। हमारे यहां किसान को महीने में 24 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। बड़े बड़े उद्योगपति

[श्री राम विलास पासवान]

एयर कंडिशंड कमरों में रहते हैं और में चौबीसों घंटे चलते रहते हैं, चौबीसों घंटे---इनके वास्ते बिजली दी जाती है। एक तरफ आप किसान की हत्या करते हैं और दूसरी तरफ उस गरीब के गांव को बिजली---

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यह वहां का किस्सा है। थाने में पुलिस ने हत्या की है।

श्री राम विलास पासवान : आप देहात में जाइये वहां बिजली के खम्भे हैं, लाइन हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं। एक बार एक्सीडेंट हो गया, बिजली की लाइन गिर गई उसको उठाने वाला कोई नहीं। और नतीजा यह हुआ कि तार को छू कर कई आदमी मर गये। आपने एक बिजली योजना चलाई है कि गरीबों, हरिजनों की बस्ती में बिजली जायगी। लेकिन कहीं बिजली नहीं है। फिर खम्भे खड़े करने का खर्चा क्यों किया ?

आपने अपनी इकोनामिक सर्वे में दिखाया है कि 60 परसेंट बिजली आज उद्योगों को दे रहे हैं और 16 परसेंट बिजली कृषि को दे रहे हैं। तो इस असमानता को आप खत्म करेंगे कि नहीं ? बिजली खराब होने के कारण अस्पताल में मरीज मर जाते हैं। डाक्टरों का कहना है कि रात में आपरेशन करते हैं लेकिन एकाएक बिजली गायब हो जाती है और रोगी मर जाता है। बिजली के अभाव में सीमेंट फैक्ट्रीज बन्द हैं जो प्रगति का प्रतीक है। खेत की हालत आपको मैंने बतायी। इसका मंत्री जी के पास कोई जवाब है ? मैं जानता हूं कि इनके पास बना बनाया जवाब होगा जिसे पढ़ देंगे। आप जब जवाब दें तो इस बात की हमेशा कोशिश करें कि आप की दृष्टि क्या है यह बतायें। क्या आपको गांवों के गरीबों के लिए दर्द है कि नहीं जिनकी करोड़ों रु. खर्च कर के आपने यहां किसान रैली में बुलाया था। वह जो आशायें ले कर गये हैं उनको पूरा करें। आप बतायें कि उस किसान के लिए आप कुछ करने जा रहे हैं कि नहीं ?

मेरा सवाल है कि क्या आप कृषि को प्राथमिकता देंगे ? और पहली प्रायरिटी कृषि के बाद जो बिजली आपके पास बचेगी उसका उपयोग उद्योगों के लिये करेंगे। क्या ऐसा आप करने को तैयार हैं ?

दूसरे जो आपने बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा था उसके मुताबिक अभी तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई, उसका क्या कारण है ? और भविष्य में इसके निदान के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

हिन्दुस्तान में जो सबसे सस्ती बिजली हो सकती है वह पन बिजली है। उसके उत्पादन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? और किसान के जो खेत सूख रहे हैं जिसके लिये मैंने कहा कि सरकार को फाटक में बन्द कर देना चाहिये, उस किसान को बिजली मिले इसके लिये आप क्या कर रहे हैं। यदि आप उसको बिजली नहीं दे सकते तो क्या किसान को सस्ती दर पर डीजल पैट्रोल मुहैया करायेंगे जिससे वह अपनी खेती कर सके ? यह मैं आप से जानना चाहता हूं।

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI): We have never claimed that we have been able to wipe out the deficit of power in the country. What we are claiming is that there has been a lot of improvement and nobody can dispute this. If you dispute this, then you are just ignoring the reality.

The present power shortage condition in the country is neither acute nor unprecedented. The shortage of power during December 1980 was about 11.1 per cent only as against 23 per cent power shortage during December 1979....

SHRI RAM VILAS PASWAN: What was the demand?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: This is our figure given by the Central Electricity Authority and we trust this figure. I do not know where from he has got his figure.

SHRI RAM VILAS PASWAN: This is from the Economic Survey.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: During January 1981 the power shortage was about 14 per cent as against 21 per cent during January 1980. The total energy generation in the country has, however, increased by 16 per cent and 9.5 per cent during December 1980 and January 1981 as compared to the corresponding period last year.

The estimated increase in the total generation of electricity during February 1981 as compared to last year was 10.3 per cent. These news obviously will blow chilly wind to your heart because this is an improvement—an achievement—of the Congress Government.

He has said about the supply of power to the agriculturists. We are very much conscious of that. We have appointed a Study Team of Central Electricity Authority, Electricity Authorities and the Rural Electrification Corporation and so on. Power distribution does not lie with us. It is with the State Government—it is with the State Eleccity Boards. It is they who are distributing the power. If we supersede them again, we will be blamed that we are interfering in the State matter. (*Interruptions*) Let them allow us to supersede them. Then I will give you the results within six months. This is the picture that I give.

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है, उसका तो कोई जवाब दिया नहीं, मंत्री महोदय खाली भाषण देकर निकल गये हैं ।

मैंने प्रश्न किया था कि बिजली की कितनी आवश्यकता है, कितना उत्पादन का लक्ष्य है और जो लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है, उसके क्या कारण हैं? पन-बिजली के लिये क्या कर रहे हैं और डीजल के लिये क्या कर रहे हैं । मेरे किसी भी प्रश्न का इन्होंने जवाब नहीं दिया है ।

श्री विक्रम महाजन : जहां तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, हमने मेन जवाब में बड़ी तफसील से बताया है कि उनको हम कन्सैशनल रेट पर बिजली देते हैं और वह कास्ट आफ जैनरेशन से भी कई स्टट्स में कम है । गुजरात सरकार ने, जब से वहां नई सरकार बनी है, उसने वहां एग्रीकलचर के लिए बिजली का रेट भी कम कर दिया है और वह जो जनता सरकार के वक्त रेट था, उससे भी कम कर दिया है ।

जहां तक एग्रीकल्चरल सैक्टर का ताल्लुक है, जो नया तरीका हमने निकाला है, वह यह है कि कम-से-कम 6, 8 घंटे किसान को बिजली दी जाये । उसका नतीजा यह होने जा रहा है कि इस वर्ष भारतवर्ष में काफी अनाज पैदा होगा जितना आज तक नहीं हुआ, रिकार्ड ब्रेक होगा । (व्यवधान) अपने किसान भाईयों को जो बिजली हमने दी है, उसकी वजह से जो नई सरकार ने नये तरीके निकाले हैं . . .

श्री राम विलास पासवान : अभी कितनी बिजली मिल रही है ?

श्री विक्रम महाजन : हर स्टेट को इंस्ट्रक्शन दी है, उन्होंने कहा है कि हम दे रहे हैं । जहां तक किसान का ताल्लुक है, यह सरकार और बिजली का महकमा टाप-प्रायटी किसानों को दे रहा है, जिसकी वजह से रिकार्ड उत्पादन हो रहा है । जैसे कि आपने देख लिया कि कितने किसान हमारे साथ हैं, जब हमने यहां किसान रैली की थी ।

जहां तक पावर जेनरेशन से ताल्लुक है, अभी वजीर साहब ने बता दिया कि कितनी पावर इन्क्रीज हुई है । जहां तक हरियाणा का ताल्लुक है, वहां कुछ कमी थी, वहां कुछ झगड़ा था पावर इंजीनियर्स का और सरकार का, लेकिन जहां तक बिजली का ताल्लुक है, हरियाणा में भी इम्प्रूवमेंट हुई है, फिगर्स हमने दे दी हैं ।

हरियाणा में दिसम्बर 79 में 27 परसेंट शार्टेज थी और दिसम्बर 80 में 12 परसेंट रह गई । इसी प्रकार जनवरी 80 में 50·3 परसेंट थी जो कि जनवरी, 81 में 29·2 परसेंट रह गई । यह फिगर्स इसलिए दिये हैं यह बताने के लिए कि मुल्क में हर स्टेट में बिजली की इम्प्रूवमेंट हुई है ।

[श्री विक्रम महाजन]

उत्तर प्रदेश में दिसम्बर 79 में 46 परसेंट शार्टेज थी और दिसम्बर 80 में 21 परसेंट रह गई । इतना फर्क पड़ा । जनवरी 80 में 33 परसेंट थी, जो कि 81 में 20 परसेंट रह गई ।

इस तरह से सारे स्टेट्स की तफसील मेरे पास है । बिहार में ऐसी स्थिति है जहां पर कुछ कह ही नहीं सकते । वैस्ट बंगाल में भी इसी तरह की कुछ बात है ।पावर शार्टेज की वजह यह है कि जितनी जरूरत है, उतनी कैपेसिटी नहीं है । पिछले तीन चार सालों में नई कैपेसटी इनस्टाल करने की कोशिश नहीं की गई । कई प्राजेक्ट्स के शिड्यूल तीन चार साल स्लिप कर गये हैं । इस लिए मुल्क में उतनी कैपेसिटी नहीं लग सकी, जितनी चाहिए थी । इसका सेहरा भी इन लोगों के सिर पर है । मुल्क के कुछ पार्ट्स में बारिश कम होने से रेजरवायर्ज में पानी का लैवल कम हो गया । वजीर साहब ने बताया है कि एग्रीकल्चरल सैक्टर के लिए पावर सप्लाई को मानिटर करने के लिए स्पेशल टीम्ज भेजी गई हैं और चालू प्राजेक्ट्स को वक्त पर पूरा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे मुल्क भर में इम्परूवमेंट हो गई है और हो रही है ।

श्री मनोहर लाल सैनी : (कुरुक्षेत्र) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि बिजली का उत्पादन बढ़ा है और इस बारे में उन्होंने फिगर्ज भी दिये हैं । लेकिन किसानों को बिजली नहीं मिल रही है । तो फिर बिजली कहां जा रही है ? मंत्री महोदय ने किसान रैली का भी जिक्र किया है । किसान रैली में जो लोग आये थे, वे किसान नहीं थे और जो किसान थे, वे बिजली मांग रहे थे । लोहारू में बिजली की मांग करने वाले पन्द्रह हजार किसानों पर गोली चलाई गई, जिससे दो आदमी मारे गये, सैंकड़ों घायल हुए और सैंकड़ों गिरफ्तारियां की गई । उन लोगों को बिजली नहीं मिल रही है ।

इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ एम.एल.ए. ने चार्ज लगाया है और इस बारे में प्रधान मंत्री को लिखा है, कि हरियाणा के एक मंत्री ने साढ़े सात लाख रुपया ले कर बिजली का खराब एक्विपमेंट खरीदा है, जिससे बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है ।

मंत्री महोदय ने सारे हिन्दुस्तान के फिगर्ज दे कर बताया है कि बिजली का उत्पादन बढ़ा है और कहा है कि हरियाणा में भी बढ़ा है । लेकिन वह कहां जा रहा है ? जब जनता पार्टी का राज्य था और चौ. देवीलाल मुख्य मंत्री थे, तो कृषि सैक्टर को 22 घन्टे बिजली मिलती थी । आज मंत्री महोदय सारे मुल्क में छः घन्टे बिजली देने की बात करते हैं । हरियाणा में किसानों को तीन घन्टे भी बिजली नहीं मिल रही है । परसों, 9 मार्च को, श्री रामावतार शास्त्री और दो एम पीज वहां गये और उन्होंने देखा कि बिजली की मांग करने वाले किसानों पर लाठी-चार्ज हुआ और उन्हें मार-मार कर जेल में बंद कर दिया । एक किसान, टेक चन्द, को जान से मार कर सड़क पर डाल दिया गया ।

किसान रैली के समय हरियाणा के मुख्य मंत्री फरीदाबाद गये और उन्होंने फैक्टरी वालों से कहा कि अगर वे किसान रैली के लिए आदमी भेजें, तो मैं किसानों को बिजली काट कर तुम्हें दूंगा । इसके मुताबिक किसानों की बिजली काट कर फैक्टरियों को दी गई । मंत्री महोदय साफ बतायें कि हरियाणा में कितनी बिजली फार्मिंग सैक्टर को एक्चुअली दी जा रही है, अगर नहीं दी जा रही है, तो क्यों नहीं दी जा रही है ।

कन्जम्पशन की एक मिनिमम लिमिट रखी गई है, जिसका मतलब यह है कि किसान को इतनी बिजली की खपत करनी पड़ेगी, और अगर वह नहीं करेगा, तो उसे उतने चार्जिज देने पड़ेंगे । किसानों से वे चार्जिज वसूल किये जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिल रही है और उन की फसलें सूख रही हैं । क्या सरकार इलेक्ट्रीसिटी एक्ट में यह एमेन्डमेंट करेगी कि

अगर बिजली न मिलने से किसान की फसल सूख जाये, तो उसे सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जायेगा ? क्या मंत्री महोदय हरियाणा में फार्मिंग सैक्टर को पूरी बिजली दिलवायेंगे ? बिजली की मांग को लेकर किसानों का जो आन्दोलन चल रहा है, रिप्रेशन के द्वारा उसको दबाने के बजाये क्या सरकार उन्हें बिजली देने की व्यवस्था करेगी ?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: Mr. Speaker, Sir, it is a fact that Harayana has been suffering from problems of low capacity utilisation on both its thermal plants at Feridabad and Panipat. The average plant load factor which had reached 43 per cent in December, 1980 declined to 29 per cent by the end of February, 1981 due to technical and local difficulties. The States Government is aware of the problem and the State Electricity Board is taking necessary steps to improve the performance of the thermal units.

Despite the poor performance in these two months, Haryana's total generation of electricity during the period from April 1980 to February 1981 has been more than doubled to what it was in the corresponding period of 1979-80. The demand for power in the winter months reached at particularly a higher level in the States of Northern Region due to the requirements of rabi crops. Sir, I can assure the hon. Member that tomorrow I am going to hold Power Ministers Conference of the Northern Region where I will also invite the concerned Chief Ministers. I can assure the hon. Member that whatever utmost is necessary for the cultivators and the agricultural sector, will certainly be done.

श्री मनोहर लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि हरियाना में फार्मिंग सेक्टर को कितनी बिजली दी जा रही है?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has already replied to your points.

SHRI MONOHAR LAL SAINI: Sir, he has not said about the farming sector.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: About the farming sector, we have already given directives to all the State Electricity Boards and we are also taking follow-up action in regard to the directives as to whether they are being obeyed or not. Over and above, I can assure the hon. Member that tomorrow we are holding conference for this purpose.

(*Interruptions*)

SHRI R. P. GAEKWAD (Baroda): Sir, with the improved water suply, with the efficient Government like the present one, why should we compare our performance with the previous Governments? Their performance has been proved beyond doubt. The entire nation knows what their performance was. I think the present Government should try to elevate themselves above all these things and try to attain the maximum efficiency in all the departments, partcularly n the Energy Department. The two young intelligent Ministers can definitely improve the efficiency further on the energy side, and supply adequate energy to the verious States. I have a few points which I would like to put for the Minister's consideration. In regard to the State of Gujarat, no doubt, water supply to the farmers is adequate. But water supply is not provided at the right time. For a good farming, the time of water supply provided is extremely important for good crops. I think quite a lot of area which is under cultivation suffers because water supply is not provided at the proper time.

Another point which I would like to make is about the staggering supply of power to the various industries. There is no criterion fixed for the supply of power of staggering basis. There are many industries which do not want staggeding supply of power but still they are getting the supply. Now, what directive has the Central Government has given to the State Governments in regard to the implementation of staggering policy of power supply to different States? I want to know whether all these points have been taken into consi-

[Shri R. P. Gaekwad]

deration before taking into consideration the question of staggering policy in regard to the power supply to the various industries.

Another point is that the transmission loss of power is shown at 40 per cent. Now, this is a very high percentage. In a country like United States of America, the transmission loss is about 20 per cent. Forty percent transmission loss is extremely high. The Ministry should look into this and take immediate steps to see that the transmission losses are lessened.

I would like to know from the Minister what steps have been taken to eliminate these difficulties through financial assistance and improvement in efficiency?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHOUDHURI: The Hon. Member is aware that at the present moment, the deficit of Gujarat in the matter of electricity is only 16.4 per cent. The performance of the Gujarat Electricity Board is very good and excellent. The only bottleneck has been that from time to time we have not been able to supply coal to them and I have no doubt whatsoever that if we are able to supply them the coal as we are able to supply them today, the performance will improve. And, there is enough scope of improvement in all the State Electricity Boards and the capacity utilization must go up. If it does go up, I think, we will be able to be self-sufficient in power. But unfortunately all that is necessary today has not been done. I am not blaming anybody, but that is what it is.

With regard to the distribution system, as such we have not given any guidlines to the State Electricity Boards. But it is the directive of the Prime Minister to look into the agricultural sector and small scale sector properly. Accordingly, we have directed all the State Electricity Boards to give utmost importance to agricultural sector as also to small scale sector.

About staggering of the distribution, it is the internal matter of the State Electricity Boards and normally we do not interfere unless a specific complaint comes to us. When a specific complaint comes to us, we sit with the State Government and try to evolve a formula, otherwise normally we do not.

As far as transmission losses are concerned, I entirely agree with the hon. Member and we are not happy with the prevailing situation, but if we can have the 400 KV national grids, of which we are thinking, I can assure the hon. Members that the transmission losses would be limited.

SHRI ZAINUL BASHER (Ghazipur): I have gone through the statement of the hon. Minister and there is no doubt about it that the situation has considerably improved. But so far as the agricultural sector is concerned, satisfactory results are not coming out. The hon. Minister has given proper directions for the increase in power generation and he has also chalked out certain good programmes and schemes for the increase of power generation in the near future. But the situation as at present in most of the States is very alarming. Particularly, a mention was made about Haryana. I come from Uttar Pradesh. The situation is very grave there. The electricity authorities and the hon. Minister of State has hold us that six hours electricity is given almost in every State. But the fact is not this, Sir. Hardly two to three hours of electricity is given in Uttar Pradesh. In Bihar, Rajasthan, Harayana also two to three hours of electricity is given and that too during the night. In this cold season, you can imagine the farmers coming out during the night in the darkness. What will they do?

Rajasthan State is under the grip of a famine. I was told that only 50 per cent of the electricity is being provided in Rajasthan. Their normal consump-

tion is 160 lakh megawatts, but now they have been provided only 80 lakh megawatt electricity.

AN HON. MEMBER: Not lakh.

SHRI ZAINUL BASHER: 80 lakh units per day, when they need 160. Only 50 per cent of Rajasthan's normal requirement is being met and that State is under the grip of a severe famine about which a mention has been made in this August House.

It is our good luck, Sir, that due to the blessing of the God we are having good crop. But there are certain areas even now in UP, Bihar and other States, where some crops are in danger because of the lack of irrigation. And irrigation is not possible without power. If you don't arrange power now within this week to the farmers in so many States, there is a danger that 20—25 per cent of crop will be damaged. We are saying that good crop is coming out. No doubt we are having a very good crop this year. But if you don't provide electricity within this week—I am warning the Government through you—considerable damage will be done. And Sir, I would like to know what action the Government is going to take? I have been told by the Hon. Minister that he is convening a Conference of the Chief Ministers of Northern States. Whether he is going to instruct them, to request them? And if they are helpless. then that will he do? The UP Chief Minister, for instance will plead his helplessness. He has no electricity to give the farmers. What the Hon. Minister will do for UP? In the same way Rajasthan Chief Minister will plead his helplessness; Haryana Chief Minister Will plead his helplessness. Then what the Hon. Minister will do when the States are unable to provide electricity? What the Centre will do and in what way they are going to help the State Governments?

Another point Sir. We cannot progress whether it is in the agricultural sector or in the industrial sector without sufficient power. Power is the crux of our development and it has to be exploited wherever we find it. But there are a large number of hydro-electric projects which are not being exploited because of the inter-State disputes. Dispute regarding the utilisation of hydro-power.

13.00 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Power will give intoxication also.

SHRI ZAINUL BASHER: There is inter-State rivalry for the exploitation of hydro-potential. What immediate action are the hon. Minister and the Government going to take in this matter, i e. to settle the differences, if any; and what are the other steps which they are going to take?

Our coal stock is concentrated in certain parts of the country. There is difficulty in the transportation of coal to different power stations located far away in the South, West, North and East. And the coal contains more of ash percentage in our country. Along with coal, power, we have to transport ash also to other countries. It is not economical. It is advisable, as the Rajadhyaksha Committee has also recommended, that power stations, at least thermal power stations, are located at pit-heads where coal is found. Power can more easily be transported, than coal. And it is cheaper. It will be possible only if power generation is taken away from the States; and the Central Government deals with it. What action is Government going to take in this matter? Are they contemplating to take at least the generation part of power, in Centre's hands?

What action is Government going to take, as I have already said, to give power to Rajasthan, Haryana and U.P. —when the Chief Ministers plead helplessness and say that they cannot do it.

One more question, about the Singrauli power station belonging to the NTPC. Has it been started or not? How much power from the NTPC's Singrauli power station is being supplied to Uttar Pradesh?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: So far as Rajasthan is

[Shri A. B. A. Ghani Khan Chaudhuri]

concerned, when RAP is okay, the shortage is 13.9 per cent. And when RAP is not okay, the shortfall is much more because there is no supply there. Actually, that creates a lot of difficulties for us, and also for Rajasthan. With regard to UP, the present shortfall is 21.9 per cent. It was something like 46.2 per cent in 1979. Now things have improved. But they have not improved as they should have. for this, we are going to discuss this matter tomorrow.

With regard to the Central directive, if any State does not listen to our directive, I can assure you that I will stop their rural electrification. I will not give them.

AN HON. MEMBER: Who will suffer then? Only people and farmers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now Motion for Election to Committee.

SHRI ZAINUL BASHER: Sir, the Minister has not given a reply.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now item 11

13.04 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE COIR BOARD

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): On behalf of Shri Charanjit Chanana, I beg to move:

"What in pursuance of sub-rule (1) (e) of rule 4 of the Coir Industry Rules, 1954, the members of the House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Coir Board for a term to be specified by the Central Government."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-rule (1) (e) of rule 4 of the Coir Industry Rules, 1954, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Coir Board for a term to be specified by the Central Government."

The motion was adopted.

13.06 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

(i) ACCUMULATION OF WATER IN VILLAGES IN SURATGARH TEHSIL, RAJASTHAN

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न वक्तव्य देता हूं:

राजस्थान की सूरतगढ़ तहसील में घग्घर बाढ़ का पानी जी.एफ.सी. नहर द्वारा तथा राजस्थान नहर की आर.डी. 165 के अस्केप से पानी छोड़ कर 18 डिपरेशन पानी से भर दिये गये हैं और इस पानी का निकास नहीं किया गया है और यह 30 किलोमीटर के लगभग लम्बी, चार किलोमीटर चौड़ी तथा 20 फुट गहरी झील बन चुकी है। जहां यह पानी भरा हुआ है, उसके बन्धे रेत के टीले हैं। इन बालू रेत के टीलों में से पानी रिसता है, झरता है और इस झील के उत्तरी साइड में उपजाऊ जमीन है और इन बालू रेत के किनारों के पास लगभग 22 गांव बसे हुए हैं। इन गांवों में बड़ोपल, किसनपुरा, मानकथेड़ी जिलानियां, ढाढियांवाली बिलकुल पानी से घिर गये हैं। यहां तक कि जिलानियां और ढाढियांवाली गांव खाली कर दिये हैं। सेमें से तमाम मकान गिर गये हैं और इन गांवों की जमीनों में सेमे का पानी भर गया है। खेती तथा फसल नाम की कोई चीज नहीं है और फसल की जगह ऐरा ही ऐरा नजर आ रहा है। इन गांवों के किसानों की जमीन सेमे के पानी में डूब गई है। ये लोग बिना घर और बिना जमीन के हो गये हैं। इन किसानों की हालत देखते ही बनती है। इनके पास गुजारे का कोई साधन नहीं है। इस वर्ष बड़ोपल, मानकथेड़ी गांव के